RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण एवं प्रबन्धन

Naresh kumar

M.A (Political Science), NET Qualified

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, राजनय, संयुक्त राष्ट्र संघ।

ABSTRACT

"यदि सुरक्षा की वास्तविक गहराई और व्यापक परिकल्पना को नहीं समझा जाएगा तो न समूची चुनौतियों का आभास होगा और न हमारे पास कोई समग्र नीति होगी। सुरक्षा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। हमारा देश प्रतिवर्ष दो बार मानसून का अनुभव करता है और हमें अच्छी तरह पता है कि वर्षा के समय मित्र के छाते का आश्रय लेने पर हमें कैसा व्यवहार करना पड़ता है। मित्र के छाते का आश्रय लेने पर बड़ी सावधानी के साथ मित्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है नहीं तो पूरी तरह लथपथ हो जाने का भय बना रहता है।"

शोध प्रविधि :–

इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए आंकड़े/तथ्य द्वितीयक स्त्रोतों से जुटाए गए हैं। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तर्क प्रस्तुत किए हैं जो शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा ज्ञान से प्राप्त किए है। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति "वीरभोग्या वसुन्धरा" की पक्षधर है। कायर व्यक्ति पृथ्वी का उपभोग नहीं कर पाते हैं। भारतीय दर्शन में शिव की जो परिकल्पना है उसके तहत शिव सर्व कल्याणकारी हैं लेकिन यह कल्याणकारी शिव शक्ति के अभाव में असहाय है। शक्तिहीन शिव की कहीं कोई महत्ता है ही नहीं और इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर के रूप का भी प्रतीक है। इसका भावार्थ यह है कि समाज, राष्ट्र और मानवता का कल्याण तभी हो सकता है जब कल्याणकारी चेतना के पीछे शक्ति का पूर्ण सम्बल हो।

शक्ति ही अन्ततः कल्याणकारी चिन्तन की रक्षा करने में समर्थ होती है। सर्वकल्याणकारी चिन्तन और सर्वकल्याणकारी सिद्धान्तों की रक्षा करने के लिए शक्ति का आश्रय लेना ही होगा। भारतीय मनीषियों की मान्यता भी रही है। यह शक्ति कभी दुर्गा है, कभी काली, कभी महाकाली और कभी कात्यायनी। इसके अभाव में मानवता का न तो कल्याण संभव है और न ही उत्कर्ष।

राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। बम्बई के बमकांड से लेकर पुरूलिया में हथियार गिराने तथा मुम्बई में आतंकवादियों के हमले जिसमें सेना और पुलिस तमाम अधिकारी और जवान शहीद हुए एवं कारगिल में घुसपैठ की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थल से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समुद्र तक भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था अभेद्य नहीं है।

याद रखना होगा कि शत्रुओं की ओर से निरन्तर आक्रमण का खतरा बने रहने की स्थिति में आर्थिक उदारीकरण से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि तब न तो विदेशी पूँजी का निवेश होगा न ही देश में उच्च कोटि की तकनीक से युक्त उद्योग लग सकेंगे।

मध्य एशिया के वर्चस्व के संघर्ष को 19 वीं शताब्दी में 'ग्रेट गेम' या महान खेल की संज्ञा दी गयी। शतरंज का वही खेल आज न केवल अनवरत रूप से जारी है बल्कि यह पहले से कहीं अधिक जटिल और तेज हो गया है क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या अब कहीं अधिक हो गयी है। तब के ब्रिटिश रूसी संघर्ष में आज अमेरिका, रूस, तुर्की, चीन, ईरान, पाकिस्तान सहित कितने ही देश फंस गये हैं।

याद रखना होगा कि जब आठवें दशक में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करके पश्मिची शक्तियों को शह देकर मात देने की रणनीति बनायी थी, उसी स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान ने अपने को अमेरिका के पालने में डालकर न केवल सैन्य साज सामान प्राप्त किया बल्कि अपने आणविक कार्यक्रम को भी गति प्रदान की थी। यही नहीं उसने अफगानिस्तान में सामरिक गहराई प्राप्त कर पाकिस्तान को एक महान इस्लामी शक्ति के रूप में भी विकसित करने का स्वप्न देखा था। आज भी पाकिस्तान इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पाकिस्तान के उद्देश्य इस बात से भी जाहिर हो जाते है कि 1992 में ही उसने उरबेक किरगिज राजमार्ग को करामेरस राजमार्ग से जोड़ने के कार्य को पूरा करने का इरादा व्यक्त किया था। यह मार्ग अफगानिस्तान से होकर जाएगा जिससे पाकिस्तान को अपनी सामरिक गहराई उजबेकिस्तान तक बढ़ाने में सफलता मिलेगी। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान की सहायता से कैसे पीछे हट सकता है और क्यों न यह चाहे कि मध्य एशिया में सऊदी–तुर्की–पाकिस्तान की योजनाओं के अनुरूप कार्य हो। ईरान चूँकि इन इरादों का समर्थन नहीं करता इसलिए वह इस्लामी कट्टरवादी है।

यह एक शुभ लक्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी भारत ने अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को गतिमान बनाए रखा है और थल सैनिक और वायु सैनिक किस्म के प्रक्षेपास्त्रों के नवीनतम संस्करणों का परीक्षण निर्बाध गति से जारी है। फिर भी अभी यह पूर्णतः दावे से नहीं कह सकता कि भारत सरकार प्रतिरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह मजबूत है। बाहरी शत्रुओं में पाकिस्तान की हमारा शत्रु नहीं है और भी अनेक राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत को अपना शत्रु मानते हैं। और तो और अमेरिका सरीखा राष्ट्र भी भारत को अपना वास्तविक मित्र मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि अमेरिका ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति ईमानदारीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया होता तो वह उस प्रकार की नीति पर नहीं चल रहा होता जिस प्रकार की नीति पर वह वर्तमान में चल रहा है।

यह सही है कि विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के इस दौर में अमेरिका भारत में पूँजीनिवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। यह भी सच है कि भारत में जिन अप्रवासी भारतीयों ने विभिन्न उद्यमों और उद्योगों में धन लगाया है और उद्योगों के वायदे किये हैं वे भी सबसे ज्यादा अमेरिका में रहने वाले या वहां के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन इसका अर्थ और तात्पर्य क्या यह होना चाहिए कि बढ़े हुए व्यापार और तकनीकी आदान–प्रदान का एक अदृश्य जैसा लालच देकर अमेरिका किसी भी किस्म की दादागीरी हमारे ऊपर करेगा और हम झेलते रहेंगे? यह भी ठीक है कि अमेरिका का महाशक्ति बने रहना ज्यादातर बल्कि कुल मिलाकर इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई और देश संसार के किसी कोने में क्षेत्रीय शक्ति बनने की ओर भी ना बढ़ सके।

दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है – शान्ति या अशान्ति – जो भी हो, उससे पूरे सात समन्दर पार बसे अमेरिका को क्या दिलचस्पी हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? वियतनाम और कम्बोडिया में उसने जो काम किया और अभी कुछ वर्ष पूर्व हमारे पड़ोस में ईराक में उसने जो किया है वह क्या वह शान्ति यज्ञ था?

याद रखना होगा कि अमेरिका महाशक्ति बाद में है पहले एक व्यापारी देश है। अमेरिका का महाशक्ति होना तथा बने रहना भी बहुधा इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी आर्थिक शक्ति और उपकार शक्ति वास्तव में कितनी है? ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार में उसके सॉस, पेप्सी, चिप्स और कोकाकोला यदि नहीं बिकेंगे तो 'नासा' में शोध और जासूसी उपग्रह छोड़ने के लिए डालर कहां से आयेंगे।

अमेरिका परमाणु अप्रसार के माध्यम से निःशस्त्रीकरण की बात कर रहा है लेकिन वहीं दूसरी ओर वह पाकिस्तान के सैन्यीकरण में मदद करता रहा है। अमेरिका परमाणु अप्रसार और परीक्षण सम्बन्धी सन्धियों की मनमानी व्याख्या कर रहा है और परमाणु शक्तियाँ उसका समर्थन कर रही हैं ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के मामले में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च वरीयता देना तथा इन सन्धियों का विरोध करना और परमाणु विकल्प खुला रखने की बात कहना आवश्यक हो जाता है। सच्चाई यह है कि परमाणु अप्रसार तथा परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की आड़ में परमाणु शक्तियाँ विश्व में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है।

जब हम इतिहास के गलियारे की ओर कदम रखते है और पलट कर अतीत के इतिहास पर नजर डालते है तो यह साफ दिखाई देता है कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य न तो आणविक प्रसार को रोकना है न इस्लामी कट्टरवाद को। उसके यदि सचमुच यही उद्देश्य होते तो वह सऊदी अरब जैसी कठपुतली सरकार को लगातार समर्थन और इस्त्राइल के परमाणु कार्यक्रम को नजरअंदाज करके पश्चिमी एशिया में जनतांत्रिक शक्तियों का केवल इसलिए विरोध न करता कि वे खाड़ी क्षेत्र में तेल पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस्लामी उष्मा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष अरब राष्ट्र का निर्माण।

उन्नीसवीं सदी से आज तक एशिया में पहले ब्रिटेन, फिर पश्चिमी खेमे और बाद में ब्रिटिश अमेरिकी गठजोड़ का प्रमुखतम उद्देश्य रूस को हिन्द महासागर के 'गर्म पानी' तक पहुँचने से रोकना ही रहा है। आज ईरान को अपना प्रमुख शत्रु घोषित करने के पीछे भी यही भावना काम कर रही है, जिसके कारण डॉ॰ मुसद्दिक की सरकार का तख्ता पलटा था और ईरान के शाह को बहाल किया गया था।

आस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की साम्राज्यों की समस्याएं आज तक नहीं सुलझ पायी हैं। पश्चिमी एशिया और यूरोप को दो–दो विश्व युद्धों के बाद भी ये चैन नहीं लेने दे रही हैं। सोवियत संघ के विघटन और महान खेल के जटिल होने के कारण एशिया ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप भी एक लम्बे संघर्ष के भंवर में फंस गया है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

एक गम्भीर प्रश्न है हमारी सुरक्षा के बीच सूराखों का। पुरूलिया में हथियार गिराये गये, समुद्री रास्ते से आंतकी मुम्बई तक पहुँचकर हमला कर गये, भारत पाक सीमा पर वर्ष 2012 में पाकिस्तान ने एक लम्बी सुरंग खोद डाली, कारगिल में भी ऐसा ही हुआ–इन सभी ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था किसी भी दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित नहीं है।

याद रखना होगा कि जब आर्थिक भ्रष्टाचार होता है तो उससे बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी से ही रंगदारी, आतंकवाद पैदा होता है जो कि अन्ततः राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बन जाता है। किसी देश की सेना, अर्द्ध सेना या सीमा शुल्क विभाग – इन सबका भ्रष्टाचार देश की समूची सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। भ्रष्ट सेना लड़ने के काबिल नहीं रहती। भ्रष्ट न्यायालय न्याय नहीं दे सकता। भ्रष्ट पुलिस बचाव तथा कानून व्यवस्था पालन करने/कराने के काबिल नहीं रहती। इन तथ्यों पर विशेष गौर किया जाना चाहिए।

चीन ने तिब्बत में जो आणविक प्रक्षेपास्त्र खड़े किये हैं उनका निशाना मुम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद और कानपुर आदि हैं। चीन बर्मा की सेना को ताकतवर बना रहा है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 40 किमी. उत्तर कोको प्रायद्वीप पर एक विशाल सैन्य अड्डा बना रहा है।

सितम्बर 1993 में भारत–चीन सीमा पर सैनिक तनाव घटाने के लिए एक समझौता हुआ। कुछ सुरक्षा विश्लेषक इसे समूचे एशिया में अपने तरह का पहला शस्त्र नियंत्रण समझौता मानते हैं। इस अवधि में कई ऐसी बातें हुई जिनसे यह संकेत मिलता था कि भारत व चीन ने अपने वर्तमान और भविष्य में बेहतर सहयोग के प्रयासों को पुराने विवादों और झगड़ों से अलग कर लिया है किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में "विगत" कभी समाप्त नहीं होता। भारत व चीन अपने विस्तृत क्षेत्रीय विवाद न तो भूल सकते हैं और न ही छोड़ सकते हैं। यह एक जीवित "विगत" है जो मैत्रीपूर्ण समझौता होने तक रहेगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि चीन–भारत युद्ध सन्निकट है। विवादों का हल शान्तिपूर्ण तरीके से हो सकता है। आपसी विश्वास के जो उपाय किये जा रहे हैं उनसे क्षेत्र सम्बंधी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी इसलिए वे स्वागत योग्य हैं। फिर भी भू–राजनीति के वृहत्तर संदर्भ में भारत–चीन सहयोग के बीच में आने वाली बाधाओं में कुछ ऐसी है जो क्षेत्रीय विवादों से कहीं बड़ी है। चीन द्वारा पाकिस्तान को एम–II मिसाइलें तथा 5000 आणविक चुम्बक छल्लों को देने जैसी घटनाओं पर बड़ी सावधानी से नजर रखने की जरूरत है। बुरे दिनों में कभी भी चीन–पाक सुरक्षा संबंधों के परिणाम हमारे लिए भयानक हो सकते हैं। यद्यपि अमेरिकी–पाकिस्तानी संबंधों ने तो कई उतार–चढ़ाव देखे हैं। पाकिस्तानियों ने कभी–कभी अमेरिकी प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता पर सन्देह भी प्रकट किया है, किन्तु चीन व पाकिस्तान के परस्पर संबंधों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता।

सैनिक मोर्चे पर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। जिन सैनिकों को कम से कम पखवारे में एक बार गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, उन्हें छः माह तक ऐसा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। वायु सेना, जल सेना तथा थल सेना तीनों ही सेनायें आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना कर रही है और यही कारण है कि जो टैंक भारतीय थल सेना को मिल जाने चाहिए थे वे समय सीमा गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल सके हैं। सोवियत संघ का विघटन भी इस समस्या को गम्भीर बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम अभी अपने शैशव काल में है जबकि पाकिस्तान ने चीन से प्रेक्षपास्त्र प्राप्त कर लिए हैं।

बम्बई में 1993 में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें करीब 15 किलोग्राम आर.डी.एक्स. का इस्तेमाल हुआ था। 1993 से लेकर अब तक हमारे दुश्मन देश कितने किलोग्राम आर.डी. एक्स. भारत भेज चुके हैं यह कोई नहीं जानता किन्तु हाल में हुई धरपकड़ से करीब आधा दर्जन राज्यों में आर.डी.एक्स. बरामद हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बना लेने तथा इन हथियारों के निर्माण के लिए चीन से सहायता प्राप्त करने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को मंच पर आकर हवा में तलवार भांजने की नहीं बल्कि परमाणु हथियारों के निर्माण की आवश्यकता है। यह ठीक है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग किसी के हित में नहीं होगा लेकिन इतना अवश्य है कि परमाणु हथियार प्रतिरोध का कार्य करते हैं।

याद रखना होगा कि जिस देश के पास नाभिकीय अस्त्र रहेंगे उस देश पर कोई शत्रु तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वह पूरी सावधानी के साथ इस कदम का आगा–पीछा न सोच ले। एक नाभिकीय शक्ति किसी दूसरी नाभिकीय शक्ति पर तभी आक्रमण करेगी जब उतरजीविता की मार्मिक समस्या उठ खड़ी हो।

हमारा देश प्रतिवर्ष दो बार मानसून का अनुभव करता है और हम भलीभांति जानते हैं कि वर्षा के समय किसी मित्र के छाते का आश्रय लेने पर कैसा व्यवहार करना पड़ता है। अपने मित्र के साथ कदम से कदम मिलाकर बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है नही तो पूरी तरह लथपथ हो जाने का भय बना रहता है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अगर सुरक्षा की वास्तविक गहराई और व्यापक परिकल्पना को नहीं समझा जाएगा तो न समूची चुनौतियों का आभास होगा और न हमारे पास कोई समग्र नीति होगी। सुरक्षा प्रबन्धन एक सतत प्रक्रिया है।

वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक ढाँचे से भारत का लक्ष्य देश की आर्थिक–सामाजिक विकास की दिशा में आगे ले जाना तथा रक्षा व तकनीकी विकास के स्तर पर विश्व के प्रमुख देशों की कतार में शामिल करना होना चाहिए।

समय की माँग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा एजेन्डा होना चाहिए तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस पर गम्भीर चिन्तन तथा सार्थक बहस की जानी चाहिए।

आज हमें वास्तविक सुरक्षा संस्कृति पैदा करने की आवश्यकता है। सुरक्षा का आयाम व्यापक है और यह शीर्ष स्तर पर विशिष्ट प्रबंधन की मांग करती है। यह समझना होगा की समस्त सुरक्षा चुनौतियों का सैनिक प्रतयुतर नहीं दिया जा सकता। वर्तमान स्थिति पर पैनी नजर तथा भविष्य की संभावनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं आंकलन में निरंतरता ही सुरक्षा प्रबन्धन का मूलाधार है।

सन्दर्भ सूची :

1. दिनेश चन्द्र पाण्डे, द्वि–ध्रुवीयता में गुटनिरपेक्षता, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1978, पृ० 210.
2. पी.एस. जयराम, इण्डियाज नेश्नल सिक्योरिटी एण्ड फॉरन पॉलिसी, ए.बी.सी. पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1987, पृ० 83
3. आर.एस. पाण्डेय, भारत के लिए हिन्द महासागर की सामरिक चुनौतियाँ– एक मूल्याकंन प्रतियोगिता दपर्ण, मई 2007, पृ० 1808.
4. यू.आर.घई एव ंके.के. घई इण्टरनेश्नल पॉलिटिक्स, न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कंपनी, जालन्धर, 2010, पृ० 292.
5. आर.एस. पाण्डेय, भारत के लिए हिन्द महासागर की सामरिक चुनौतियाँ– एक मूल्याकंन, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, मई 2007, पृ० 1808.
6. वही, पृ0 1808–09..
7. आर. एस यादव भारत की विदेशनीति : एक विश्लेषण, किताब महल, इलाहबाद, 2002, पृ 73.
8. आर.एस. पाण्डेय, भारत के लिए हिन्द महासागर की सामरिक चुनौतियाँ– एक मूल्याकंन, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, मई 2007, पृ० 1809.
9. दीपक कोहली, जैविक हथियारों की घातकता एवं निवारण, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, जून 2008, पृ0 2000.
10. पी.एस. जयरामू, इण्डियाज नेश्नल सिक्योरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी, पूर्वोदृत पृ० 90.

RRIJM 2015, All Rights Reserved